मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कोटा, जोधपुर एवं जयपुर संभाग के भाजपा जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली।

हमारे दो साल कांग्रेस के पांच साल पर भारी, सरकार की उपलब्धियों से कांग्रेस को दें करारा जवाब-भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कोटा, जोधपुर एवं जयपुर संभाग के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की

- **मुख्यमंत्री ने कहा, कार्यकर्ता की निष्ठा ही संगठन की शक्ति है, कार्यकर्ता जनता और सरकार के बीच कड़ी बनें व सरकार की योजनाएं जन-जन तक पहुँचाएं।**
- **मुख्यमंत्री ने इस दौरान बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की।**

जयपुर, 6 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोटा, जोधपुर एवं जयपुर संभाग के भाजपा जिला अध्यक्षों एवं मंडल अध्यक्षों सहित, कार्यकर्ताओं के साथ संगठन से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक की शुरूआत में मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां, अशोक परनामी, सांसद सी.पी. जोशी, राजेन्द्र गहलोत एवं पूर्व सांसद नारायण लाल पंचारिया उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्त्ता की निष्ठा ही संगठन की मजबूती का आधार है और यह मजबूती ही हमारी शक्ति है। संगठन के कार्यों को धरातल पर पहुंचाने में प्रदेश से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वे जनता और सरकार के बीच कड़ी बनें और इन योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की नीति साफ एवं स्पष्ट है। हमारी सरकार ने सिर्फ दो साल में ही कांग्रेस की पिछली सरकार की तुलना में कई गुना काम किए हैं। यमुना जल समझौता, रामजल सेतु लिंक परियोजना तथा गंगनहर के सुदृढ़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों से प्रदेश में पानी की भरपूर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। हमारी सरकार ने पहले ही साल में राइज़िंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट का आयोजन करके 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए, जिसमें से 7 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। अब तक लगभग 92 हजार युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। दिसम्बर माह में और एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग एवं 15 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दी जाएंगी।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एसआईआर के लिए बीएलए की नियुक्तियां भी की गई हैं। सभी पदाधिकारियों को सुनिश्चित करना है कि वे बीएलए का बीएलओ एवं मतदाताओं के साथ समन्वय एवं सम्पर्क स्थापित करें।

रेल्वे देश में नौ विशेष ट्रेनें चलाएगी

नयी दिल्ली, 06 दिसंबर। रेलवे ने निजी विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने के कारण देशभर में फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए नौ विशेष ट्रेनों का परिचालन करने और 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है।

- **इंडिगो संकट के मद्देनज़र रेल्वे ने यह कदम उठाया है इसी के साथ 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 कोच और जोड़े जाएंगे।**

रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है हवाई यात्रा बाधित होने के कारण अचानक काफी संख्या में यात्रियों ने रेलवे की ओर रुख किया है।

यात्रियों की इस तत्काल बढ़ी हुई मांग को देखते हुए नौ विशेष ट्रेनों का परिचालन करने का फैसला किया गया है। वहीं, देशभर की 37 प्रीमियम ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़े हैं, जिससे हजारों की संख्या में अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हो गयी हैं।

'सत्ता पक्ष में बैठे लोगों का मकसद नेहरु को बदनाम करना है

सोनिया गांधी ने यह भी कहा इन लोगों का लक्ष्य नेहरु को मिटाना मात्र नहीं, बल्कि उस आर्थिक, सामाजिक राजनैतिक नींव का नष्ट करना है जिस पर हमारा राष्ट्र बना है

- **सोनिया का यह बयान राजनाथ सिंह की उस टिप्पणी के जवाब में आया जिसमें उन्होंने कहा था कि नेहरु सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे पर पटेल ने ऐसा नहीं करने दिया।**

नई दिल्ली, 06 दिसंबर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने बीजेपी पर करारा अटैक किया है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी का मुख्य मकसद जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना है। उन्होंने बीजेपी पर भारत के पहले प्रधानमंत्री को अपमानित करने, नीचा दिखाने और बदनाम करने का आरोप लगाया।

जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया के उद्घाटन के मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि नेहरू के योगदान का विश्लेषण और आलोचना का स्वागत है। हालांकि, उनकी लिखी और कही गई बातों को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सोनिया गांधी ने नेहरू को लेकर सत्तापक्ष की ओर से टिप्पणियों पर सख्त प्रतिक्रिया दी। हालांकि, उन्होंने अपनी बात रखते हुए सीधे तौर पर बीजेपी या आरएसएस का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर कौन था, ये उनकी टिप्पणियों से साफ जाहिर था। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने दो टूक कहा कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि आज सत्ता में बैठे लोगों का मुख्य उद्देश्य नेहरू को बदनाम करना है। उनका लक्ष्य सिर्फ उन्हें मिटाना नहीं है, बल्कि वास्तव में उस सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नींव को नष्ट करना है जिस पर हमारा राष्ट्र बना है।

सोनिया गांधी की यह टिप्पणी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नेहरू सार्वजनिक धन का इस्तेमाल बाबरी मस्जिद बनाने के लिए करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। कांग्रेस ने इस दावे को झूठ बताते हुए राजनाथ सिंह पर ध्रुवीकरण फैलाने का आरोप भी लगाया था।

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि नेहरू पर हमले में शामिल समूह एक ऐसी विचारधारा को मानता है, जिसकी स्वतंत्रता आंदोलन या संविधान निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी। जिसने नफरत को हवा दी, यहां तक कि जिसके कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई। कांग्रेस सांसद ने दो टूक कहा कि आलोचना करें, लेकिन विरासत को न तोड़ें।

'विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाए या अविश्वास प्रस्ताव हम तैयार है'

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पत्रकारों से कहा इनके साथ डीके शिवकुमार भी थे

- **सिद्धारमैया ने कहा नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर मैं और शिवकुमार आलाकमान का निर्णय मानेंगे।**

बंगलूरू, 06 दिसंबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि अगर विपक्ष 8 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उनकी कांग्रेस सरकार इसका सामना करने के लिए तैयार है। उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने दोहराया कि नेतृत्व के मुद्दे पर वह और शिवकुमार दोनों हाईकमान के निर्णय का पालन करेंगे।

सिद्धारमैया ने एक सवाल के जवाब में कहा, वे (विपक्ष) अविश्वास प्रस्ताव लाएं या स्थगन प्रस्ताव या कोई और प्रस्ताव, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार खुली किताब की तरह है, पारदर्शी सरकार है। हम किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने साफ किया कि पार्टी ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में अभी तक कोई चर्चा या फैसला नहीं किया है।

कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर से शुरू होकर इस महीने की 19 तारीख तक चलेगा। नेतृत्व परिवर्तन से जुड़े प्रश्न पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा, डीके शिवकुमार और मैं दोनों हाईकमान के किसी भी निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे।

इससे पहले दिन में बंगलूरू में शिवकुमार ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विधान सौध बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के बाद हवाई अड्डे तक छोड़ा। इस दौरान दोनों के बीच संभावित बातचीत को लेकर नेतृत्व परिवर्तन पर अटकलें तेज हो गई थीं।

राज्य में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का आधा हिस्सा 20 नवंबर को पूरा होने के बाद, मुख्यमंत्री बदलने की चर्चाओं के बीच सत्ताधारी दल के भीतर शक्ति संघर्ष देखने को मिला था। इन चर्चाओं के बीच हाल ही में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने हाईकमान के निर्देश पर एक-दूसरे के आवास पर नाश्ते की बैठकें की थीं।

राष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनके 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

मोदी ने इससे पहले सोशल मीडिया एक्स पर बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लिखा, ''महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर का स्मरण करते हैं। उनका दूरदर्शी नेतृत्व और न्याय, समानता और संविधानवाद के प्रति डॉ. अम्बेडकर की अटूट प्रतिबद्धता भारत की राष्ट्रीय यात्रा का मार्गदर्शन करती रहेगी। उनसे मानवीय गरिमा को बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूत करने की पीढ़ियों ने प्रेरणा ली है। ईश्वर करे कि उनके आदर्श हमें एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर करते रहें।''

सीतालक्ष्मी सहित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सीबीआई को गोपनीय सूचना मिली थी कि आईटीएटी जयपुर बेंच में लंबे समय से अपीलों को तय करने में धांधली चल रही है। इस पर सीबीआई ने आईटीएटी जयपुर बेंच में रिश्वत लेकर फैसले देने के मामले में न्यायिक सदस्य सीता लक्ष्मी व वकील राजेन्द्र को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया था। वहीं, सीता लक्ष्मी की कार से 30 लाख रुपए और दलाल राजेन्द्र के घर से 80 लाख रुपए बरामद किए थे। इसके अलावा, सीबीआई ने मामले में पक्षकार और रिश्वत देने वाले कोटा निवासी मुज्जमिल को भी गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य अधिकारी कमलेश राठौड़ को भी गिरफ्तार किया। सीबीआई ने कमलेश से भी 20 लाख रुपए बरामद किए थे।

रिज़र्व बैंक द्वारा ''रैपो रेट'' ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से ई.एम.आई. कम होती है और कर्ज़ की मांग बढ़ती है। लेकिन इस बार इस कटौती का असर उम्मीद से धीमा हो सकता है। बैंक अभी भी डिपॉजिट ग्रोथ से जूझ रहे हैं जो कर्ज़ की तेज बढ़त के मुकाबले धीमी है। इसलिए नई जमा आकर्षित करने के लिए ऊँची ब्याज दरें बनाई रखनी पड़ रही हैं। इस संरचनात्मक कमी की वजह से बैंक इस कटौती का पूरा लाभ तुरंत ग्राहक तक नहीं पहुँचा पाएंगे। जो लोग लोन रेट में तुरंत गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें राहत तुरंत मिलने के बजाय धीरे-धीरे मिल सकती है।

वित्तीय बाज़ार की प्रतिक्रियाएं भी सावधानी का संकेत देती हैं। शेयर बाज़ारों ने रेट-सेंसिटिव सेक्टरों में मामूली बढ़त के साथ प्रतिक्रिया दी, जबकि करेंसी की चिंताओं के कारण व्यापक सूचकांक कमज़ोर रहे। बॉन्ड बाज़ार ज़्यादा उत्साहित थे, लेकिन वहाँ भी इस सोच के कारण उत्साह कुछ कम था कि आर.बी.आई. की रेट कटौती की प्रक्रिया सीमित रहेगी। सेंट्रल बैंक का न्यूट्रल रुख बनाए रखना यह बताता है कि वह तेजी से लगातार कटौतियों की दिशा में नहीं जा रहा, बल्कि हर मीटिंग में पॉलिसी को एक-एक करके एडजस्ट कर रहा है।

वैश्विक हालात तीसरा बड़ा जोखिम हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, और ग्लोबल इन्वेस्टर की जोखिम उठाने की इच्छा, ये सभी कारक भारत के बाहरी संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी आर.बी.आई. की आगे की कटौतियों की गुंजाइश कम कर सकती है। इसी तरह अगर वैश्विक निवेशक सुरक्षित बाज़ारों में पैसा लगाना शुरु कर दें, तो भारत जैसे उभरते बाज़ारों को अपनी मुद्रा को संभालने के लिए, ढील देने के बजाय, दखल देना पड़ेगा।

घरेलू निवेश के रुझान भी अनिश्चितता बढ़ाते हैं। आर.बी.आई. 2025-26 के लिए 7.3 प्रतिशत की मज़बूत जी.डी.पी. ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट अभी भी ठीक नहीं है। अगर खपत तेजी से नहीं बढ़ी तो सरकार को ही पूँजीगत खर्च का बोझ उठाना पड़ सकता है। इकोनॉमिस्ट चेतावनी देते हैं कि अकेले मॉनेटरी ईजिंग से इन्वेस्टमेंट रिवाइव नहीं हो सकता, जब तक कि इसे मज़बूत डिमांड, कम इनपुट कॉस्ट और बेहतर ग्लोबल स्थितियों का सपोर्ट न मिले।

आर.बी.आई. का हालिया रेट कट भारत के मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स में विश्वास को दिखाता है। फिर भी, आगे का रास्ता सतर्कता की मांग करता है। महंगाई फिर से बढ़ सकती है, रुपया और कमज़ोर हो सकता है, और ग्लोबल मुश्किलें बिना किसी चेतावनी के तेज़ हो सकती हैं। पॉलिसी बनाने वालों, बिज़नेस और आम लोगों के लिए मैसेज साफ़ है: राहत का आनंद लें, लेकिन उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहें।

केस तय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर जल्द फैसला हो सके। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बकाया मामले खत्म कर दिए जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि लिटिगेशन (मुकदमेबाजी) एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लोगों को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा और विश्वास है।

सीजेआई ने कहा, नए मामले दायर होंगे, लेकिन पुराने मामलों का निपटारा होना भी जरूरी है। मध्यस्थता का भी इस्तेमाल किया जाएगा और ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मैं एक सख्त और स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए है और सामान्य मुकदमेबाजी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में पर्याप्त जगह है। हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि वह अकेले इस काम को नहीं कर सकते और उन्हें इसमें अन्य जजों का भी सहयोग चाहिए।

मनमाने हवाई किराए पर केन्द्र ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लागू रहेंगी, जब तक स्थिति पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती। इस निर्देश का उद्देश्य बाजार में मूल्य निर्धारण अनुशासन बनाए रखना, संकट में फँसे यात्रियों का शोषण रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि जिन नागरिकों को तुरंत यात्रा करनी है, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, छात्र और मरीज शामिल हैं, उन्हें इस दौरान वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े।''

मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह हवाई किरायों की निगरानी वास्तविक समय के आंकड़ों के माध्यम से करता रहेगा और एयरलाइनों और ऑनलाइन यात्रा प्लेटफार्मों के साथ मुस्तैदी से समन्वय करेगा।

एक अलग बयान में, मंत्रालय ने कहा कि उसने इंडिगो से सभी यात्रियों के रिफंड बिना किसी देरी के जारी करने का निर्देश दिया है। बयान में कहा गया, ''मंत्रालय ने यह आदेश दिया है कि सभी रद्द या प्रभावित उड़ानों की रिफंड प्रक्रिया को 7 दिसम्बर 2025, रविवार, रात 8:00 बजे तक पूरी तरह से पूरा कर लिया जाए। एयरलाइनों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे उन यात्रियों से कोई पुनर्निर्धारण शुल्क न लें, जिनकी यात्रा योजनाएं उड़ानों के निरस्तीकरण के कारण प्रभावित हुई थीं।''

दिन की शुरुआत में, इंडिगो की सैकड़ों घरेलू उडानें रद्द कर दी गईं, क्योंकि एयरलाइन का व्यापक संकट पांचवें दिन भी जारी रहा। रोजाना 2,300 उड़ानों का संचालन करने वाली इंडिगो, जिसके उड़ान बेड़े में 400 से अधिक विमान हैं, ने संचालन में विघटन के कारण अपनी समयबद्धता में भारी गिरावट देखी है, और यह संकट और कई दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इस संकट का मुख्य कारण पायलटों की कमी है, जिसका पूर्वानुमान योजना की विफलताओं के कारण नहीं किया गया। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।

राष्ट्रपति के भोज में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और वे उसमें शामिल होंगे। जब उनसे दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं के नाम आमंत्रित लोगों की सूची में नहीं होने के विषय में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आमंत्रण भेजने का आधार क्या रहा है, लेकिन वे (थरूर) आमंत्रित होने पर निश्चित रूप से सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

थरूर ने यह स्पष्ट किया कि एक सांसद के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्र की बेहतरी के लिए, सरकार के साथ सहयोग करना और काम करना ''एक अलग विषय है,'' और इसका राष्ट्रपति भवन के डिनर के लिए आमंत्रित होने से कोई संबंध नहीं है।

थरूर ने कहा, ''इसका राष्ट्रपति भवन के डिनर के आमंत्रण से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन सच यह है कि सरकार के साथ सहयोग के सवाल पर, आप अपनी विचारधारा या सिद्धांतों को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि आप सामान्य जमीन (कॉमन ग्राउन्ड) ढूंढते हैं। मेरा मतलब है, यह लोकतंत्र का एक हिस्सा और सरकार और विपक्ष के बीच सहयोग का एक हिस्सा है - कॉमन ग्राउन्ड तलाश करना। हम कुछ चीजों से असहमत होते हैं, कुछ चीजों पर सहमत भी होते हैं, तथा जिन बिन्दुओं पर हम सहमत हैं, उन पर हमें मिल कर काम करना चाहिए।'' थरूर हाल ही में सरकार के बारे में अच्छा बोलते रहे हैं, जिससे उनकी पार्टी कांग्रेस को काफी निराशा हुई है।

लेकिन थरूर के इस तरह के बयानों और कांग्रेस द्वारा हर समय सरकार के हर कदम की आलोचना के चलते, सरकार के लिए आवश्यक था कि वह एक बड़े राष्ट्रीय सरोकार, जैसे ''ऑपरेशन सिंदूर'' के बारे में जानकारी देने के लिए विदेशों में प्रतिनिधिमंडल भेजना, के लिए विपक्षी दल के किसी नेता को आमंत्रित करे और थरूर को ऐसी एक टीम का सदस्य बनाया गया था, लेकिन यह प्रश्न तो खड़ा होता ही है कि क्या केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद (थरूर) कभी कोई बड़ा कदम उठाएंगे?

थरूर ने इस प्रश्न का एक सटीक और रहस्यमय जवाब दिया, ''मुझे नहीं पता कि यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है। मेरा मतलब है, मैं कांग्रेस पार्टी का सांसद हूं। मुझे चुनाव जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। किसी भी अन्य स्थिति के लिए बहुत अधिक चिन्तन और अन्य अनेक पक्षों और बिन्दुओं पर विचार करने की जरूरत होगी।''

उन्होंने कहा कि उनके पास एक काम है- मतदाताओं के लिए काम करना और वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें।

उन्होंने कहा, ''आज भी, डिनर से पहले चल रही बातचीतों में, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ चीजों के बारे में यहाँ कुछ सरकारी अधिकारियों से चर्चा कर रहा था, जिनसे डिनर पर मेरा सम्पर्क हुआ था। यह सब अपने लोगों, अपने मतदाताओं, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करने का प्राण-तत्व है। यह (हमारी) राजनीतिक जिम्मेदारी है।''

इंडिगो ने 1500 से ज्यादा उड़ानें संचालित की

नयी दिल्ली, 06 दिसंबर। पायलटों की कमी और परिचालन संबंधी समस्या का सामना कर रही निजी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने शनिवार को 1,500 से अधिक उड़ानों का संचालन किया।

इंडिगो की रद्द उड़ानों की खबरों और परेशान यात्रियों की तस्वीरों के बीच

- **एयरलाइन्स ने बताया कि शनिवार को रद्द उड़ानों की संख्या भी घट गई।**

एयरलाइंस ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उसने शुक्रवार को 700 से अधिक उड़ानों का परिचालन किया था, और शनिवार को आधी रात तक यह संख्या 1,500 से अधिक हो जायेगी।

उल्लेखनीय है कि रोजाना 2,300 से अधिक उड़ानों का संचालन करने वाली इंडिगो की शुक्रवार को एक हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द रही थीं। एयरलाइंस ने कहा है कि आज रद्द उड़ानों की संख्या घटकर 850 से कम रह गयी। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि शनिवार को इंडिगो ने अपने नेटवर्क में शामिल 138 में से 135 शहरों के लिए उड़ानें भरीं।

'इंडिगो एयरलाइन्स को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **ये कॉरपोरेट हाउस की आपसी प्रतिद्वंदिता में निर्णय लिए जाते हैं, तो आम आदमी का हित गौण हो जाता है और निर्णय शतरंज की चाल जैसे तर्क पर आधारित हो जाते है।**

प्रमुख एयरलाइन और रूझान वाला कंपनी समूह, राजनीतिक विमानन ढांचे में तेजी से विस्तार कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, जिससे समग्र पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो रहा है।

विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट भारत की विमानन शासन व्यवस्था में एक गहरी संरचनात्मक कमी को उजागर करता है। एक एयरलाइन द्वारा क्षमता का एकाधिकार और एक कॉर्पोरेट समूह द्वारा प्रमुख हवाई अड्डा संपत्तियों पर प्रभुत्व स्थापित करने के बाद, सरकार ने प्रभावी रूप से संतुलन बनाने की अपनी क्षमता खो दी है। ऐसे माहौल में, नीतियों के संकेत सार्वजनिक हित की बजाय कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्धा से आकार लेते हैं।

ऐसे व्यवधान सीधे जनता पर असर डालते हैं, बिना किसी प्रणालीगत सुरक्षा के। विश्लेषकों का कहना है कि सरकार की चुप्पी चिंता का विषय है। ऐसा लगता है कि प्रभावित यात्रियों को आश्वस्त करने के लिए निर्णायक कदम उठाने की बजाय, प्राधिकरणों को लगता है कि राजनीतिक शर्मिंदगी से बचने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की अधिक चिंता है। इस संघर्ष में सबसे बड़ी हार आम लोगों की हुई है। किराए में वृद्धि, एक साथ फ्लाइट्स कैंसल होना, आखिरी समय में शेड्यूल में बदलाव और हवाई अड्डों पर फैली अराजकता ने यात्रियों को एक कॉर्पोरेट खींचतान का बेजुबान शिकार बना दिया है। रिफंड, पुनर्भरण या सुरक्षात्मक उपायों की कोई स्पष्टता न होने के कारण विमानन प्रणाली में सार्वजनिक विश्वास निचले स्तर तक पहुंच गया है। विमानन क्षेत्र के एक प्रमुख विशेषज्ञ, जिन्होंने भारतीय वायु सेना के साथ तीन दशकों से अधिक समय तक काम किया है, ने कहा कि जब तक सरकार एक पारदर्शी विमानन सिद्धांत नहीं बनाती और ''उपभोक्ता-प्रथम'' नियम लागू नहीं करती, तब तक जनता असुरक्षित तथा शक्तिशाली निजी संस्थाओं और सरकार के बीच जकड़ी हुई, जो उनसे निपटने में संकोच करती है।

बाबू लाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने आरोपी की मन:स्थिति को देखते हुए उसे जिला जेल से केन्द्रीय कारागार में शिफ्ट करने आदेश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान, बाबूलाल कटारा अदालत में पेश हुआ। कटारा ने अदालत को बताया कि उसे जेल में कुछ लोगों से जान का खतरा है। इसके अलावा, अत्यधिक तनाव के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर होने की जानकारी भी दी। इससे पूर्व कटारा की ओर से उसके अधिवक्ता भानु प्रकाश शर्मा ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि गत 28 नवंबर को जिला कारागार से कटारा ने अपने बेटे को फोन कर कुछ लोगों की ओर से परेशान किये जाने की जानकारी दी थी। कटारा ने बेटे को यहां तक कहा कि यदि अब उसके पास फोन नहीं आए तो वह यह मान ले कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है। इस पर उदयपुर निवासी बेटे ने इसकी जानकारी उन्हें दी और सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि कटारा जेल में बंद हैं और व्यक्तिगत रूप से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश करने में असमर्थ है।

इसलिए बतौर अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि कटारा की मानसिक दशा स्थिर नजर नहीं आ रही है और उसमें भारी तनाव और डिप्रेशन दिख रहा है। हालांकि प्रार्थना पत्र में कटारा को दूसरे जेल में शिफ्ट करने की गुहार नहीं है, लेकिन सुनवाई के दौरान कटारा ने अपने आप को उदयपुर जेल में शिफ्ट करने की मौखिक गुहार की। वहीं अदालती आदेश की पालना में विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने कटारा के आरोपों को लेकर गोपनीय सीलबंद रिपोर्ट पेश की।

ममता बनर्जी के मुस्लिम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- **ममता जी के लिए हुमायूं कबीर द्वारा प्रस्तुत चुनौती का जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर, उसने मुस्लिम नेता के रूप में सफलता पा ली, जिसकी काफी संभावना लगती है, तो ममता जी का राजनीतिक अवसान भी सकता है।**

लेकिन अब चुनौती बंगाल की उसी मिट्टी से उठ रही है, जिसे ममता अपना राजनीतिक गढ़ मानती हैं। अब यह कहकर बचना संभव नहीं कि कबीर बाहरी हैं। उन्हें स्थानीय जमीन पर ही कबीर की बातों का जवाब देना होगा, जिसमें कबीर यह आरोप लगा रहे हैं कि असल में ममता ही मुसलमानों के खिलाफ़ हैं, और उनके काम इसका प्रमाण हैं।

ममता अब तक मुस्लिम वोट बैंक के दम पर आगे बढ़ी हैं, क्योंकि भाजपा राज्य में हिंदू वोटों का बड़ा हिस्सा लेने में सफल रही है। मुस्लिम मतदाता लगातार चुनाव- दर- चुनाव भारी संख्या में ममता का समर्थन करते रहे हैं।

बदले में ममता ने भी उन्हें भरपूर तुष्टिकरण दिया। वे मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुईं, मुस्लिम अंदाज़ में कपड़े पहने, बालों को साड़ी में ढककर, और कभी-कभी मुस्लिम मुहावरों या धार्मिक शब्दों का गलत-सही उच्चारण भी किया, जिससे सुनने वालों को काफी मज़ा भी आता था।

उन्होंने कई बार हिंदू त्योहारों और परंपराओं के खिलाफ बयान दिए। त्योहारों पर रास्तों और टाइमिंग पर रोक लगाई। भाजपा ने इन बातों का विरोध किया और हिंदू समुदाय को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन इन विरोधों से ममता को कोई राजनीतिक नुकसान नहीं हुआ।

अब ममता को उसी ज़मीन से अपने अंत की शुरुआत दिख सकती है, जहाँ उन्होंने तुष्टिकरण का बीज बोया था। अगर उन्हें यह नया खतरा झेलना पड़े, तो यह उनके लिए विडंबना होगी। पहले भी इंडियन सैक्युलर फ्रंट जैसे मुस्लिम समूह, जो खुद को ''सैक्युलर'' बताते थे, उभरने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन टिक नहीं पाए। लेकिन अब, एक कड़े इस्लामवादी संगठन को बंगाल के मुसलमानों के सामने विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908